

पत्रावली पेश हुई। वकील इनका पक्ष (प्रायोजक) आग्रह में
इसमें पक्ष की कहस सुनी गई।

हस्तागत अपील क्रमांक द्वारा 225 RT Act
के तहत इसका खर्च उभारने वाली, काउन्सिल के आदेश दि. 20.3.12
तहसीलदार काउन्सिल के तहत सरकार के विरुद्ध पेश की गई।
अपीलाधीन आदेश में अपीलदार परकार नहीं है क्योंकि
वे क्रमांक द्वारा 96 CPC के अन्तर्गत बलिष्ठ कमील सुनाने
सहित कर रहे हैं।

अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप C)
के प्राप्ति की पालना में राजकीय शक्ति में चालू करीबी
रान्ते का राजस्व रिपोर्ट में कानून कानून के अन्तर्गत में
तहसीलदार काउन्सिल द्वारा प्रस्तुत किये गए इसका उभारने वाली,
काउन्सिल ने पारित किया है। आदेश के अन्तर्गत से ही
स्पष्ट होता है कि आदेश कानून व्यवस्था (SDD) काउन्सिल की
दोषिता में राजा भारतवासी कानूनिक के तहत पारित कोई
करिया नहीं है। आदेश में राजस्व काउन्सिल के तहत
कराना में कानूनिक उभारने वाली की दोषिता में राजकीय
शक्ति की रान्ते के रूप में राजस्व रिपोर्ट में कानून
दस्तावेज के अन्तर्गत से पारित किया है जिन्की
कमील न्यायालय द्वारा नहीं हुनीजा तहसील।
एक ही शक्ति वकील कानूनिक द्वारा प्रस्तुत मांग डिक्लेयर
कमिशन, जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण 126/2018
कानूनिक के अन्तर्गत राजा राज्य काउन्सिल राजस्व कानूनिक
क्रमांक द्वारा 75 PLR Act, जिन्में इस प्रकार के अन्तर्गत
में पारित किया कानूनिक की सुनाने की रान्ते से कानूनिक
प्रस्तुत हुई है। हस्तागत कमील इस न्यायालय के अन्तर्गत
में नहीं होने के कारण ग्रहण किया जाते प्रमाण नहीं है।
अपीलाधीन सक्षम न्यायालय में एक तहसील में चालाकानी कानून
है। स्वतंत्र है। हस्तागत कमील अन्तर्गत के अन्तर्गत से परे होने
के कारण खारिज की जाती है।

पत्रावली क्रमांक शुभार लेका नंबर से कानून
है। काउन्सिल कानूनिक दफ्तर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

